1	2	3
23	त्रिपुरा	2236
24	उत्तर प्रदेश	27648
25	पश्चिम बंगाल	42582
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	176
27	चंडीगढ़	758
28	दादरा और नगर हवेली	40
29	दिल्ली	5084
30	दमन व दीव	18
31	लक्षद्वीप	49
32	पांडिचेरी	1078
	कुल . .	318973

विवरण--2

सरकारी सेवाओं में नियुक्त किये गये विकलांग कर्मचारियों को दी जा रही सुविधायें ।

(i) विभिन्न कार्यों की पहचान की गई है जो विकलांग व्यक्तियों के लिये उपयुक्त है ।

(ii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये (i) समूह घ में ही (ii) समूह घ से ग तथा (iii) समूह ग में ही आरक्षण किया जा रहा है ।

(iii) दृष्टिहीन तथा अस्थि विकलांग को मूल वेतन के 5% तक अथवा 100 रुपये जो भी कम है, वाहन भता दिया जाता है ।

(iv) विकलांग व्यक्तियों को आवास प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश की पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जन जातियां

4652. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विलुप्त प्राय जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर-लोगों के अस्तित्व को बचाये रखने और उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए वर्ष 1992-93 तक किन-किन कार्यक्रमों को लागू किया गया है ;

(ख) 1990-91 में 1991-93 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है और राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि व्यय की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकार ने इन जनजातियों के कल्याणार्थ लागू किए जा रहे कार्यक्रमों का कभी कोई मूल्यांकन कराया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन जनजातियों के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण कराने के लिए की जा रही कार्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति समूहों के रूप में पहाड़ी और बिरहोर को शामिल करते हुए सात आदिवासी समूहों की पहचान की गई है। इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं, ताकि इन समूहों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इन योजनाओं में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन

हेतु आदानों की सप्लाई शामिल है। आदिम जनजाति समूहों के बीच शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। आदिवासी उप योजना रणनीति के अंतर्गत इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इन समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। 1971 तथा 1981 की जनगणना के बीच तुलना करने पर यह पता चलता है कि इन समूहों की जनसंख्या में गिरावट नहीं आ रही है। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	1971	1981
पहाड़ी कोरवार	13488	16860
बिरहोर	738	886

(ख) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में पहाड़ी करवार और बिरहोर सहित आदिम आदिवासी समूहों के विकासार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता में से कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई वार्षिक निर्मुक्ति निम्न प्रकार है : —

वर्ष	निर्मुक्त राशि (लाख रुपयों में)	
1990-91	255.20	
1991-92	282.92	
1992-93	6785.01	(आदिम जनजाति समूहों के लिए आवंटन सहित संपूर्ण विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों को निर्मुक्त कर दी गई क्योंकि वर्ष के दौरान अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया।

राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई धनराशि में से खर्च किये गये व्यय के बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ग) कल्याण मंत्रालय ने 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के पहाड़ी कोरवार के संबंध में रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किये हैं। 1992-93 में मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति समूहों के विकास संबंधी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उपलब्धियों के संबंध में एक अध्ययन करने का कार्य भारत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली को सौंप दिया गया था। इन संगठनों की रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं। मध्य प्रदेश सरकार का आदिवासी अनुसंधान संस्थान भी अपने राज्य में आदिम जनजाति समूहों के विकास के संबंध में अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर रहा है।

(छ) राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य में पहचान किये गये आदिम जनजाति समूहों के संबंध में एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तथा कार्रवाई योजना को तैयार करें जिससे आदिम जनजाति समूहों की स्पष्ट वास्तविक अवस्थिति उनकी वर्तमान आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थितियां समूहों को पेश आ रही तात्कालिक समस्याएं जिन पर शीघ्र कार्रवाई करने की जरूरत है। समर्पित व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित प्रशासनिक प्रबंध, तथा वास्तविक लक्ष्यों के लिए वार्षिक प्रावस्था सहित वित्तीय आवश्यकता तथा प्रचालन में लचीलापन शामिल हो।

Sale of an infant for Rs. 500 in Assam

4653. SHRI VIRENDRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the newsitem appeared in Times of India dated 10th July, 1993 that at Siliguri a 38 year old women Malii Roy put her three months old boy for auction for Rs. 1500/- as she is unable to living up the child;

(b) whether she ultimately sold it for Rs. 500/-; and